

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 729वीं बैठक दिनांक 06/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 10562/2023 Shri Paravat Singh Tomar, Owner, M/s Tomar Builders and Contractors Private Limited, R/o A-1/8, Vinay Nagar, Sector-4, District-Gwalior (MP)-474012, Prior Environment Clearance for Keruaa Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (150000 cum per year) (Khasra No. 290), Village-Kairua, Tehsil-Bhitarwar, District-Gwalior (MP).**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 691वीं बैठक दिनांक 18/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक में परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई थी:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी के आंकलन के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी मय आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये -

1. खनन क्षेत्र की गूगल इमेज में वर्ष 2016 के बाद खनन कार्य परिलक्षित है। इस संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करें।
2. खनन क्षेत्र के निकट स्थित केनाल के दृष्टिगत निर्धारित सेटबैक देने के बाद बचे हुए खनन क्षेत्र हेतु पुर्नरीक्षित सर्फेस प्लान तथा तदनुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करें।
3. पुर्नरीक्षित प्लांटेशन स्कीम रंगीन मैप के साथ।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क़शर का उपयोग नहीं किया जायेगा। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि खनन किये गये पत्थर की क़शिंग क़हों की जावेगी तथा माईन से क़शर तक पत्थर का परिवहन किस प्रकार किया जावेगा।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 06 / 03 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Parvat Singh Tomar, Owner online**, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

- खनन क्षेत्र की गूगल इमेज में वर्ष 2016 के बाद खनन कार्य परिलक्षित है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खनन क्षेत्र की गूगल इमेज में वर्ष 2016 के बाद खनन कार्य परिलक्षित है क्योंकि 2015 से 2017 के मध्य रोड़ निर्माण कार्य के लिए अस्थायी अनुज्ञा स्वीकृत थी जिसका उत्खनन क्षेत्र का पिट का विवरण वर्तमान अस्थायी अनुज्ञा कि खनन योजना के सरफेस मेप एवं माईनिंग प्रोडक्शन प्लान में दर्शाया गया है।
- खनन क्षेत्र के निकट स्थित केनाल के दृष्टिगत निर्धारित सेटबैक देने के बाद बचे हुए खनन क्षेत्र हेतु पुर्नरीक्षित सर्फेस प्लान तथा तदानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि खदान क्षेत्र से पूर्व दिशा में एक नहर 112 मी. की दूरी पर है अतः लगभग 88 मी. का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है। खनन क्षेत्र हेतु पुर्नरीक्षित सर्फेस प्लान पूर्व अनुसार ही रहेगा क्योंकि सेटबैक छोड़ने के बाद उत्खनन कार्य पूर्व अनुसार ही है क्योंकि यह एक अस्थायी अनुज्ञा है और इसका प्रोडक्शन कार्य मात्र एक वर्ष के लिए ही है तथा तदानुसार अनुमोदित माईनिंग प्लान के सरफेस एवं प्रोडक्शन मेप में प्रोडक्शन कार्य पूर्व अनुसार ही रहेगा इसलिए इसमें कोई चैन्ज नहीं है।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार खनन क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क़शर का उपयोग नहीं किया जायेगा। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि खनन किये गये पत्थर की क़शिंग क़हों की जावेगी तथा माईन से क़शर तक पत्थर का परिवहन किस प्रकार किया जावेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि चूकि यह एक अस्थायी अनुज्ञा है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा मूवेबल क़शर के द्वारा पूर्व स्थित क़शर के पास ही सेटबैक वाले क्षेत्र में मूवेबल क़शर स्थापित करके क़शिंग कि जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 1,50,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में क़ेपीटल राशि रु. 15,22. लाख एवं रिक़रिंग राशि रु. 1,76 लाख प्रति वर्ष।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी जावें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
सी.ई.आर मद से 50,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम केरुआ के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	50,000/-
योग	50,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4680 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (शासकीय भूमि)	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर) पूर्ण सुरक्षा सहित	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
3	गांव में वितरण	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2680

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 2 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ष में किया जावेगा। अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत को निर्धारित राशि 5,14,000 और 10 परसेंट रख रखाव के लिए 51,400 राशी प्रदान कि जाएगी। (चूँकि परियोजना प्रस्तावक की गिट्टी की खदान टेम्पररी परमिट की है।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No 10273/2023 Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s Trimurti Enterprises, 190, Ajaybag Colony, District-Indore (MP)-452001 Prior Environment Clearance for Pipalkhut Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 13/5), Village- Pipal Khut, Tehsil-Mhow, District-Indore (MP)

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं बैठक दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, जियो टेग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें साथ ही यह भी निर्देश दिया कि डिया की पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार एवं प्रस्तावित योजना के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत पौधे का क्रियान्वयन प्रस्तुत करेंगे, तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री नरेन्द्र सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा (ऑनलाईन). मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेंसिंग की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	पौधा रोपण नहीं किया गया है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	आंशिक रूप से अपूर्ण है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य सहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-40000 घनमीटर/वर्ष।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.97 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.56 लाख प्रति वर्ष ।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
ग्राम केशरबर्डी शासकीय माध्यमिक विद्यालय बिल्डिंग मरम्मत कार्य	50,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (शासकीय भूमि)	शीशम , नीम,पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल,सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम,करंज,जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आँवला, मुनगा, आम, जामुन एवं अन्य प्रजातियाँ	700

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 10302/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 2.53 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 2846), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP).**

प्रकरण सेक की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 06/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Chandrabhan Yadav, Partner, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, ऑनलाईन, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, E-mail-sadguru.env12@gmail.com, Mobile-9425116626. Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 2.53 ha. (30,000 cum per year) (Khasra No. 2846), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [434659]
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं.—2846, (निजी भूमि) एरिया— 2.53 ha., नॉन फारेस्ट)
परियोजना स्थल	ग्राम—धनेरा, तहसील— करेरा, जिला—शिवपुरी (म.प्र.)

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

सैधातक सहमति	पत्र क्र०. 1658 दिनांक 19/12/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित माईन प्लान ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र०. 615 दिनांक 27/03/2023 द्वारा स्टोन कशिंग क्षमता – 30,000 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को प्रतिवर्ष 50 पेड लगाये जाने की शर्त अधिरोपित की गई थी।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 30,000 घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-30,000 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.370 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-.... श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत थनरा जिला – शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 22/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा– पक्का रोड लगभग 395 मी.
	पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 450 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक – 25 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
--	----------------------------------

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	पौधा रोपण नहीं किया गया है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित नहीं हुई है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य सहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लगभग 760 पौधे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांटे गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-30,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 15.82 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.77 लाख प्रति वर्ष ।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
वैलनेस सेण्टर के खाते में जमा किया जावेगा	60,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (निजि भूमि)	जामुन, कटहल, मुनगा, आम, सीताफल, इमली, आवंला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
4	अंकुर योजना के तहत ग्रामवासियों में वितरण हेतु	पीपल, कचनार, कदम्ब, मुनगा	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभार्थी व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

4. **Case No 10303/2023 Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 1.84 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 2842/2), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP)**

प्रकरण सेक की 701वीं बैठक दिनांक 15/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 06/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Chandrabhan Yadav, Partner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना की रूपरेखा

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Chandrabhan Yadav, Partner, M/s Sadguru Sai Granite, R/o Satyadev Nagar, Gandhi Road, 301, Satyam Residency Apartment, Gird, R K Puri, District-Gwalior (MP)-474011, E-mail-sadguru.env12@gmail.com, Mobile-9425116626. Prior Environment Clearance for Thanra Crusher Stone Quarry in an area of 1.84 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 2842/2), Village-Thanera, Tehsil-Karera, District-Shivpuri (MP) [434654]
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं.-2842/2, (निजी भूमि नॉन फारेस्ट) एरिया- 1.84 ha.,
परियोजना स्थल	ग्राम-धनेरा, तहसील - करेरा, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 1658 दिनांक 19/12/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र0. 616 दिनांक 27/03/2023 द्वारा स्टोन क्रशिंग क्षमता - 20000 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को प्रतिवर्ष 50 पेड लगाये जाने की शर्त अधिरोपित की गई थी।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर - 20,000 घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-20,000 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण ।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 758. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4. 370 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-.... श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 758. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 758. दिनांक 06/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत थनरा जिला – शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 22/05/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	. दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 652 मी. पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 482 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-16 के सरल क्रमांक – 24 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	लगभग 250 पौधा रोपण किया गया है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित नहीं हुई है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य सहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लगभग 552 पौधे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांटे गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—20,000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 14.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.62 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. **0.60** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल थानरा में फर्नीचर (दस नग बेंच एवं डेस्क) एवं दो अलमारी	60,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (निजि भूमि)	नीम, बॉस, करंज, आम, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1100
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	अंकुर योजना के तहत ग्राम पंचायत भवन एवं शासकीय स्कूल में (ट्री-गार्ड के साथ)	पीपल, कचनार, कदम्ब, मुनगा	200
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभार्थी व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठोस के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

5. Case No 10717/2023 Shri Jagdish Dangi, Lessee, Village-Padoniya, Panchayat-Padoniya, Biaora, District-Rajgarh (MP)-465674, Prior Environment Clearance for Padoniya Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 192/1), Village-Padonaya, Tehsil-Biaora, District-Rajgarh (MP)

प्रकरण सेक की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 06/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Jagdish Dangi, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Jagdish Dangi, Lessee, Village-Padoniya, Panchayat-Padoniya, Biaora, District-Rajgarh (MP)-465674, Prior Environment Clearance for Padoniya Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4,000 cum per year) (Khasra No. - 192/1), Vill-Padonaya, Teh-Biaora, District-Rajgarh (M.P). [442035].
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 192/1, एरिया- 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम- पड़ोनिया, तहसील- ब्यावरा, जिला- राजगढ़ (म.प्र.).
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. 755 दिनांक 24/08/2022.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	लागू नहीं।
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• CONTROLLED BLASTING (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया राजगढ़ का ई.सी. पत्र क्रमांक 548 दिनांक 04/07/2016.
उत्पादन क्षमता	Stone – 4,000 Cum / Year,

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 04 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 614 दिनांक 08/08/2023 अनुसार नहर-300 मी., पक्का रास्ता - 200 मी. तथा सूखा नाला - 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत- पडोनिया जिला - राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क्र. 02 दिनांक 02/10/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर पूर्व दिशा- प्राकृतिक नाला लगभग 50 मी. पर एवं उत्तर दिशा पक्का रोड लगभग 160 मी. पर है परियोजना प्रस्तावक द्वारा 40 मी. का सेट बैक प्रस्तावित किया है। उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 35 मी. की दूरी पर 24 मी. लंबा एक स्टाप डेम/रपटा है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजगढ़ के पत्र क्रमांक 912 दिनांक 03/10/2023 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया -

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित नहीं हुई है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स	अवलोकित नहीं हुई।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

में बैचस की स्थिति।	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य सहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लगभग 552 पौधे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांटे गये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 35 मी. की दूरी पर 24 मी. लंबा एक स्टाप डेम है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि स्टाप डेम से निर्धारित दूरी छोड़ते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

6. Case No 10729/2023 Shri Rajesh Thakur, Owner, R/o Ward No. 7, Devi Mohalla, Bhaisdehi, District-Betul (MP)-460220, Prior Environment Clearance for Dhudiyani Crusher Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (7684 cum per year) (Khasra No. 166/3), Village-Ghudiya Nai, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [DEIAA]

प्रकरण आज सेक की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 06/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश ठाकुर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Narendra Singh Maan, Partner, M/s TRIMURTI ENTERPRISES, 190, Ajaybag Colony, Indore (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13/5 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Ha.
स्थल	ग्राम Pipal Khut तसहील Mhow जिला Indore (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 927 दिनांक 28/04/23 के द्वारा स्वीकृत।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
ब्लैस्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लैस्टिंग प्रस्तावित है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इंदौर के पत्र क्रमांक 772 दिनांक 27/02/17 के द्वारा पत्थर-30,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-40,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 04.600 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 716 दिनांक 28/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/ स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत केशरबर्डी जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 20/04/2010 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर शासकीय नियमों/प्रावधानों अनुसार खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 40 मी.
	पूर्व पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 278 मी. .
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-46 के सरल क्रमांक-69 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	आंशिक अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण अपूर्ण है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित हुई है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचैस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य सहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लगभग 300 पौधे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांटे गये एवं लीज क्षेत्र में पौधे नहीं लगाये हैं।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि उत्तर दिशा— पक्का रोड लगभग 40 मी. की दूरी परस्थित है एवं प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है तथा नियमानुसार पक्का रोड से 200 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र छोड़ा जाता है तो लीज एरिया समाप्त हो जाता है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।

7. Case No 10730/2023 Shri Bheem Awadhiya, Owner, R/o Narmadaganj, Tehsil & District-Dindori (MP)-481880, Prior Environment Clearance for Ganeshpur Dhangaon Ryt Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5005 cum per year) (Khasra No. 99), Village-Ganeshpur, Tehsil-Dindori, District-Dindori (MP) [DEIAA] (B2).

प्रकरण सेक की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 06/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Bheem Awadhiya, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Bheem Awadhiya, Owner, R/o Narmadaganj, Tehsil & District-Dindori (MP)-481880, Prior Environment Clearance for Ganeshpur Dhangaon Ryt Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5,005 cum per year) (Khasra No. - 99), Village-Ganeshpur, Tehsil-Dindori, District-Dindori (MP) [447504] [DEIAA Case].	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 99,	एरिया— 1.00 ha., निजि भूमि (सहमति प्राप्त)
परियोजना स्थल	ग्राम— गणेशपुरा, तहसील — डिण्डोरी, जिला— डिण्डोरी (म.प्र.).	
सैधातिक सहमति	पत्र क्र0. 667 दिनांक 03/05/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	लागू नहीं।	

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Control Muffle Blasting.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया डिण्डोरी का पत्र क्र०. 899 दिनांक 31/08/2017.
उत्पादन क्षमता	Stone – 5,005 Cum / Year,
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 399 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं है, कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 399 दिनांक 08/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 399 दिनांक 08/09/2023 अनुसार नहर-300 मी., पक्का रास्ता – 200 मी. तथा सूखा नाला – 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	नगर पंचायत- गणेशपुरा जिला – डिण्डोरी का ठहराव प्रस्ताव क्र०. 08 दिनांक 02/10/2016 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा- . पक्का रोड लगभग 242 मी.
	दक्षिण दिशा- पक्का रोड लगभग 264 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा – मकान लगभग 314 मी. एवं शेड्स लगभग 180 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-102 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	आंशिक अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	लीज एरिया में लगभग 70 पौधे लगाये गये हैं
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित नहीं हुई है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचैस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य सहित साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लगभग 300 पौधे परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांटे गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-5005 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.04 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
------------------------------------	----------------

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

गणेशपुर प्राथमिक शाला में बच्चों के पेयजल हेतु वाटर फ़िल्टर एवं पानी की टंकी	15000
--	-------

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन
11. अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (निजि भूमि)	नीम, आम, जामुन, कटहल, चिरोल, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
2	भूमि ख- न- 99	आम, जामुन, आँवला, मुनगा, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	500
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, सीताफल	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठौर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

8. **Case No 10750/2023 Shri Shivkumar Yadav, Lessee, R/o H.No. 1041, Ward No. 18, Sanjay Nagar, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP)-464337,, Prior Environment Clearance for Prior Environment Clearance for Badoh Flagstone Quarry in an area of 2.00 ha. (3060 cum per year) (Khasra No. 805/4), Village-Baroh, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (M.P.).**

प्रस्तावित खदान का 705वीं बैठक दिनांक 27/12/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । बैठक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार जो की ऑनलाईन बैठक में जुड़े थे, उनकी नेट कनेक्टिविटी में बार बार व्यवधान आने से वह प्रकरण को

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे अतः समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण को सेक की आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुतीकरण का एक अवसर प्रदान किया जाये।

प्रकरण आज दिनांक 06/03/24 को पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री **Shri Shivkumar Yadav, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi **Online**, Director, AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SHIVKUMAR YADAV, Lessee, H.No.1041, Word No.18, Sanjay Nagar, Tehsil-Pathari, Vidisha (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	805/4 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village - Badoh, Tehsil - pathari, District - Vidisha (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 954 दिनांक 04/05/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन-3,060 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार फ्लैग स्टोन-3,060 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत बडोह जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक	

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

की अनापत्ति	24/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र पेड़ों से अच्छादित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा पेड़ों से अच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में दर्शाया है जिससे खनन कार्य हेतु लगभग 0.70 हे. एरिया खनन हेतु उपलब्ध होता है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाड़ी के फुट हिल में स्थित है। उत्तर दिशा— पक्का रोड लगभग 120 मी. एवं नाला लगभग 220 मी. की दूरी पर स्थित है, परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1714 दिनांक 26/09/2023 अनुसार आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टोन 3060 घन मी./वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.67 लाख प्रति वर्ष।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
ग्राम बड़ोह के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा	40,000

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

संघ में उल्लेखित राशि जमा करी जावेगी

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (शासकीय भूमि)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- खमेर, करंज, जंगल जलेबी, नीम , चिरोल, आदि।	450
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-कदम्ब, नीम, करंज, पुत्रंजीवा, जंगल जलेबी, आदि।	150
3	ग्राम वासियों को फलदार पौधे वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-, सीताफल, आम , संतरा , पपीता , आम , हाइब्रिड मूंगा, कटहल आदि।	1800
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. Case No 10751/2023 Shri Palash Vijay S/o Narendra Kumar Vijay, Lessee, R/o Ward No. 13, Nake No. 3, District-Rajgarh (MP)-465661, Prior Environment Clearance for Rugnathgarh Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (Gitti-2579, M-Sand-4421 cum per year) (Khasra No. 1/1/2), Village-Rajgarh, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP) (B2).

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

प्रकरण सेक की 705 वीं बैठक दिनांक 27/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक /03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Palash Vijay, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Palash Vijay S/o Narendra Kumar Vijay, Lessee, R/o Ward No. 13, Nake No. 3, District-Rajgarh (MP)-465661, <i>Prior Environment Clearance for Rugnathgarh Crusher Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (Gitti-2579, M-Sand-4421 cum per year) (Khasra No. 1/1/2), Village-Rajgarh, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP) [447320]</i> .
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 1/1/2, एरिया— 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम— राजगढ़, तहसील— राजगढ़, जिला— राजगढ़ (म.प्र.).
सैधातक सहमति	पत्र क्र०. 505 दिनांक 03/07/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	लागू नहीं।
खनन कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Single row Controlled Muffle Blasting (As per Parivesh Portal uploaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	Gitti - 2579, M-Sand-4421 cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 04 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार नहर-300 मी., पक्का रास्ता — 200 मी. तथा सूखा नाला — 50

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

	मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत- नेसडी जिला - राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 07 दिनांक 26/01/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा- नाला लगभग 35 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-राजगढ़ के पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **स्टोन (गिट्टी)- 2579 मी³ प्रति वर्ष एवं एम. सेण्ड - 4421 मी³ प्रति वर्ष।**
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.57 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.70 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
ग्राम रघुनाथगढ़ के विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	1,30,000/-
योग	1,30,000/-

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (शासकीय भूमि)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, मोलश्री, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , नीम आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- करंज, कदम्ब, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू आदि।	200
3	गांव में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला आदि।	600

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. **Case No 10637/2023 Shri Surya Chaurasiya, Lease Owner, R/o Ward 07, Purani Basti, Maihar, Near Hanuman Mandir, Maihar, District-Satna (MP)-485771, Prior Environment Clearance for Bathiya Stone Mine in an area of 1.736 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 504, 527, 538, 540/1, 541/1, 542/2, 545), Village-Batiya, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) -DEIAA-SEIAA**

प्रस्तावित खदान की समिति की 693वीं बैठक दिनांक 20/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजों (पुराने प्रकरण का एलओआई) के साथ प्रस्तुत किया जाये।

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री सूर्या चौरसिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अत्यंत अल्प फेन्सिंग की है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान	बेरियर जोन खुदा हुआ है

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित नहीं हुआ है।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लीज में 79 पेड लगाये गये हैं एवं 522 पेड बांटे गये।
गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी दिशा में लगभग 07 मी. पर एक हॉलेज रोड है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण पूर्व दिशा में आने जाने के लिये एक वैकल्पिक रास्ता स्थित है बटिया गांव मे से होकर परिवहन नहीं किया जावेगा। उत्तर पूर्व दिशा में 396 मी. की दूरी पर आबादी है।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-6000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.88 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 4.69 लाख प्रति वर्ष ।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये हैं। अतः 25 मी. का सेड बैंक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
ग्राम बटिया के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श कर रोगी कल्याण समिति में योगदान दिया जायेगा।	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1568 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (निजि	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन	740

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

	भूमि)	एवं अन्य फल दार स्थानीय प्रजातियाँ,	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	200
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण (ट्री-गार्ड के साथ) शासकीय विद्यालय बठिया में	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद। कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	608 20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. Case No 10725/2023 Shri Raghunandan Singh, Lease Owner, R/o 86, Laxmi Nagar, District-Jhabua (MP)-457661, Prior Environment Clearance for Jhakela Stone Mine in an area of 0.90 ha. (5820 cum per year) (Khasra No. 851), Village -Jhakela, Tehsil-Rama, District -Jhabua (M.P.) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान का समिति की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:-

1. खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करे।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

2. समिति के द्वारा सुझाव अनुसार पुनरक्षित पौधा रोपण का प्रस्ताव।
3. उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक के निर्माण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई. एम.पी में प्रस्तुत करें।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे कच्ची एवं पक्की सड़क) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 05/03/24 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Raghunandan Singh Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग कार्य अपूर्ण
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है
गारलैण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	कार्य अपूर्ण
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	लीज क्षेत्र में पौधा रोपण एवं वितरण कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 03 साल से खदान बंद है।
गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में नाला 50 मी. पर है एवं उत्तर पश्चिम दिशा में स्टाप डेम 220 मी पर है।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-5820 घनमीटर/वर्ष।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.57 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 4.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
5. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैंक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
8. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
ग्राम झकेला के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूला लगवाया जायेगा।	50,000
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्रामपंचायत झकेला के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।	60,000
ग्राम झकेला के शासकीय प्राथमिक शाला में 9 कम्प्यूटर, 9 प्रिंटर, 9 टेबल, दिया जायेगा।	50,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 810 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (शासकीय	सिरसू, नीम, बरगद, खमैर, चिरौल, सीताफल, करंज एवं	400

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

	भूमि)	अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	100
3	शासकीय विद्यालय झकेला में (ट्री-गार्ड के साथ)	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, कुसुम गुलमोहर।	20
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण (ट्री-गार्ड के साथ)	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	290
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. Case No 9113/2022 Shri Praveen Chandrapatel, Owner, Bastar Road Dhamtari District Dhamtari State Chattisgarh. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 3.14 ha. (38000 Tonne per annum) (Khasra No. 30, 32, 33, 34, 35 and 36), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bicchiya, Dist. Mandla (MP) (EIA)

प्रकरण आज सेक की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

13. Case No 10328/2023 Smt. Sangeeta Agrawal, R/o Near Bus Stand, Prithvipur, District Niwari (MP)-472336, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 1344/2), Village-Bhopalpura, Tehsil-Prithvipur, District-Niwari (MP) . DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान का समिति की 679वीं दिनांक 14/9/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । तत्पश्चात् प्रकरण का पुनः समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

18. Carbon footprint.

19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 06/03/24 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक गौरव तिवारी (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, ऑनलाईन, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ. प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग कार्य आंशिक अपूर्ण
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में पौधा रोपण नहीं पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	निर्मित नहीं पाये गये।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य के साथ साक्ष्य प्रस्तुत किये गये।
कोई अन्य शर्त	खनन क्षेत्र में 120 पौधे लगाये गये एवं 1200 पौधे वितरण किया।
गूगल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में पक्का रोड 350 मी. पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में स्थित 01 पेड काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 10 पेड अतिरिक्त लगाये जायेंगे।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—50,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.19 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.87 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
ग्राम भोपालपुरा में अधोसंरचना विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत को राशि प्रदान की जाएगी।	1,00000
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने एवं श्री अन्न योजना के प्रचार हेतु पंचायत एवं कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा ।	40,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में (शासकीय भूमि)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे: पीपल ,मोलश्री , करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, सिस्सू, नीम आदि।	800

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे: करंज, चिरोल, नीम, सिस्सू, जंगल जलेबी आदि।	100
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे: संतरा, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, आवला आदि।	3900

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से ठॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

14. Case No 10858/2023 Shri Prateek Gehlod, Owner, 23, A Keshav Nagar, District-Alirajpur (MP)-457887, Prior Environment Clearance for Baidiya Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (3135 cum per year) (Khasra No. 46/1), Village-Baidiya, Tehsil Sondwa, District Alirajpur (M.P.). [DEIAA]

प्रस्तावित स्टोन खदान का समिति की 712वीं बैठक दिनांक 10/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि माईनिंग प्लान के अनुसार खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। दक्षिण दिशा में 78 मी एवं पूर्व दिशा में खदान से 58 मी. पर पक्का रोड है, पक्की रोड से ब्लास्टिंग की स्थिति में 200 मी. प्रतिबंधित है, पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्ताव माईनिंग आफिस में प्रस्तुत किया है। समिति ने निर्देश दिये कि माईनिंग ऑफिस से संशोधित प्लान प्राप्त होने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 06/03/24 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक गहलोत, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रमुख, डीजीएम कार्यालय से दिनांक 02/01/2024 को अनुमोदित खनिज योजना (डिजिटल दस्तावेज) के पेज न. 01 पर नॉन ब्लास्टिंग रॉक ब्रेकर से खनन कार्य किये जाने का उल्लेख है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-3135 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 5.69 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.73 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
6. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि (रु. में)
ग्राम बयडिया में स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण मंडल में उल्लेखित राशि जमा की जावेगी	30,000
नजदीकी ग्रामों में जैविक खाद के उत्पादन एवं उपयोग के लाभ समझाने हेतु पंचायत के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावेगा	20,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम , खमेर , कालासिरिस,	500

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

		सिस्सू, करंज, चिरोल, सफेदसिरिस, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	70
3	ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण (ट्री-गार्ड के साथ)	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण (ट्री-गार्ड के साथ)	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1180

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

15. **Case No 10816/2023 Shri Navin Patwa, Company Secretary, M/s SAM Industries Limited, Village, Dakachiya, AB Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore (MP)-453771, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse “Shivaay LogiSpace” in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259/1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.). Cat. 8(a) Building Constructon Project.**

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse “Shivaay LogiSpace” in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259//1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.). The proposed project is falling under Project /Activity 8(a), Building and Construction Projects, Category B-2 (built-up area \geq 20000 m² and < 150000 m²) and requires Environmental Clearance (EC) from SEAC/SEIAA, M.P.

The case was presented by Env. Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. and PP Shri Naveen Patwa, Company Secretary from M/s SAM Industries Limited.

PP submitted following details on Parivesh Portal :

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/450903/2023.
2.	Project Name	Shri Navin Patwa, Company Secretary, M/s SAM Industries Limited, Village, Dakachya, AB Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore (MP)-453771, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of Commercial Warehouse “Shivaay LogiSpace” in an area of 10.009 ha. (42441.58 sq.m.) (Khasra No. 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259//1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2, 258/2/2), Village-Dakachya, Tehsil-Sawer, District-Indore (M.P.). [450903]. Cat. 8(a) Building Constructon Project.
3.	Area details as per Form -1	Total Plot Area: 54689 m2. Total Built up Area – 42441 m2. Greenbelt area (10%)– 8910 m2. Parking area – 4728 m2 Open Parking- 189 ECS.
4.	Project Proposal	New.
5.	CGWA NOC	CGWA/NOC/INF/ORIG/2023/19524 Date of Issuance 06/11/2023.
6.	Project Cost	4365 Lakhs.
7.	Undertaking No Construction start at site	PP Submit undertaking affidavit dated 27/10/2023.
8.	Lat./Log. As per Form -1	Latitude Longitude 22°51'23.13"N 75°57'0.73"E 22°51'23.37"N 75°57'5.41"E 22°51'20.34"N 75°57'13.52"E 22°51'11.88"N 75°57'7.51"E 22°51'12.64"N 75°56'58.73"E

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

		22°51'17.23"N 75°56'57.89"E
9.	NBWL Application	No
10.	Gram Panchyat NOC	Village – Dakachiya, Tehsil _ Sanwer, Distt-Indore letter no. 663 dated 17/08/2023.
11.	Building Permission	-
12.	T& CP Permission	Letter 6400 dated 08/11/2019. Copy uploaded on Parivesh Portal.
13.	Extra Treated Water	PP Affidavit submitted dated 07/11/2023. PP Apply Letter dated 27/10/2023. (Copy uploaded on Parivesh Portal).
14.	MSW NOC	PP Apply Letter dated 27/10/2023. (Copy uploaded on Parivesh Portal).
15.	DG set details	DG Set of 1x400 KVA & 320x4 KVA each.
16.	Parking details	189 ECS.
17.	Env. Consultant	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.). Valid up to 19/08/2024.

During presentation PP submitted that this is a warehouse project / Logistic park project. On Google image some sheds are existing within project area PP submitted that these sheds are proposed for demolition hence committee asked PP to furnished C& D details . moreover , some trees are exist in the project area, committee suggested that PP shall considered project feasibility and proposed minimum tree felling, existed within project area.

After presentation PP was asked to submit following information of the project for further consideration of the project:

- Carbon emission foot print analysis shall be submitted with quantification from different sources and their management plan.
- Submit C& D details of demolition of the sheds.
- Tree inventory of the project area with status of conservation..
- Considered project feasibility and proposed minimum tree felling, existed within project area.
- Show lay out map on the Goggle earth.
- Parking space shall be depicted on colour lay out map.
- PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
- Proposed Green belt area shall be shall be depicted on colour lay out map
- Revised CER, which shall be need based as suggested by the committee.
- Ecological damage assessment w.r.t to the proposed tree felling.
- Basis of Cold storage – means which gas shall be used .
- PP shall submit PFR.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

The project proponent submitted clarification 06.02.2024 on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the SEAC 710th meeting dated 05.01.2024. Hence, this case was scheduled for query reply presentation.

The query reply was presented by Env. Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. along with PP's representative Shri Navin Patwa On-line, from M/s Samrddhi Civicon Private Ltd. wherein submitted that

- Carbon emission foot print analysis submitted with quantification from different sources and their management plan.
- Submitted C& D details of demolition of the sheds.
- There are 150 trees existed in the site. In 150 trees, 50 trees shall be uprooted, we have obtained permission from Local Authority. We have deposited the 25000 Rs to the Local Authority for complementary plantation as per rule.
- 50 trees will be uprooted. We have obtained permission from Local Authority. We have deposited the Rs. 25000 to the Local Authority for complementary plantation as per rule.
- Layout map of the project site is submitted.
- PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP, proposal for filter press.
- Proposed Green belt area shall be depicted on colour lay out map.
- Submitted revised CER.
- Regarding Ecological damage assessment Rs. 25000 shall be deposited to the Local Authority for complementary plantation as per rule.
- PP submitted that in the proposed warehouse there will be no provision of cold storage.
- PP submitted PFR (Conceptual Plan).

PP submitted quantification of Carbon Footprint for proposed project and remediation measures, for this purposes in addition to PP's proposal Committee asked PP to incorporated adoption of older growth trees, plantation of minimum 1000 trees, soil & water conservation, protection and regeneration work in Deoguradiya through DFO within 01 year. The plant species may included Bargad, Peepal, Pakar, Gular, Tinsa, Achar, Beeja, Haldu, Dahiman etc. Regarding Ecological damage assessment Rs. 25,000 shall be deposited to the Local Authority for complementary plantation as per rule.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for "Proposed Construction of 'ShivaayLogiSpace", at Plot No.- 255/1/1, 255/1/2, 255/1/3, 255/1/4, 255/1/5, 255/3, 255/4/1, 255/4/2, 255/4/3, 255/4/4, 255/4/5, 255/5/1, 255/5/2, 255/6/1, 255/6/2, 255/7/1, 255/7/2, 255/8/1, 255/8/2, 259//1/1, 259/1/2, 259/2/1, 259/2/2, 259/3/1, 259/3/2, 259/4/1, 259/4/2, 259/5, 258/1/2k, 258/2/1, 258/1/1, 258/1/2/1, 258/2/1/kh/258/1/2/2 & 258/2/2 Village- Dakachya, Tehsil- Sanwer, District- Indore, Madhya Pradesh.** Cat. 8(a) subjects to the following special conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low-lying area. The top soil shall be used for greenery development.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 05 Diesel power generating sets 400 kVA*1 and 320*4 kVA proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low Sulphur Diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- xi. The gaseous emission from DG sets 400kVA*1 nos., and 320*4 kVA shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase will be 57.58 KLD out of which 18.92 KLD is fresh water requirement and 40.4 KLD will be the total recycled water generated, out of which 38.66 KLD recycled water will be used for flushing (29.75 KLD) & Horticulture (8.91 KLD).
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF & CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built-up area and storage capacity of minimum one day of total fire water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 13 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about $13.66\text{m}^3/\text{hr}$. Mesh will be provided at the roofs that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWA.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Sewage shall be treated in the MBBR followed by ultra filtration based STP (Capacity-170 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 170 KLD capacity (based on MBBR followed by ultra filtration) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 30% of the demand load or as per the state level /local building bye-law's requirement, which is higher.
- vi. PP shall be explored the possibility of laying of solar panels on warehouse roofs to generate the green energy for their in –houses uses, their e- vehicles etc.

VI. Waste Management

- i. Total waste 456.25Kg/day, this consist all types of wastes (as Organicwaste 273.75 Kg/day and non- organic waste 136.87 Kg/day), Inert waste 45.62 Kg/day, E-waste 486.9Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste (0.4 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

VII. Green Cover

- i. Total 1000 trees shall be planted in the area of 8910 m² (10 % of total plot area) within the project site, with following plantation scheme.

Proposed Plantation		
Sr. No.	Local Name	No. of trees
1	Putranjeeva	50
2	Amaltas	80
3	Ficus venjamin	50
4	Bargad	50
5	Ashoka	50
6	Sita Ashok	80
7	Gobar Champa	60
8	Pakhad	70
9	Jamun	80
10	Molshree	85
11	Neem	84
12	Kusum	131
13	Sitafal	130

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

Total	1000
--------------	-------------

- ii. There are 150 trees existed in the site. In 150 trees, 50 trees shall be uprooted, we have obtained permission from Local Authority and deposited the 25000 Rs to the Local Authority for complementary plantation as per rule.
- iii. For Ecological damage assessment Rs. 25,000 shall be deposited to the Local Authority for complementary plantation as per rule.
- iv. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- v. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- vi. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stock piled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

- iv. Total 189 nos. proposed Parking's arrangement as in which Car Parking-101 ECS, Truck Parking-88.
- v. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporation Environment Responsibility

- i. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 470.0 Lacs as capital and Rs. 53.0 Lacs as recurring cost for this project.
- ii. For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs.120.0 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

S.N	Particulars	Total in Lacs	First year	Second Year	Third Year
1	Distribution of School Uniform and school kit in Govt School Dakachya and Amli Kheda & other adjoining villages.	10	4	3	3
2	Distribution of medical equipment's in the Dakachya PHC's and Dakachya Anganwadi	20	10	5	5
3	Distribution of medical equipment's in the nearby veterinary hospital	30	10	10	10
4	Adoption of older growth trees, plantation of minimum 1000 trees, soil & water conservation, protection and regeneration work in Deoguradiya through DFO within 1 year.	50	30	20	-
5	Installation of solar panels at Govt High School, Dakachya	10	5	5	-
	Total Lacs	120	84	18	18

- iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly reports.
- v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC).
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. **Case No 11224/2024 Shri Rajesh Chandra, Jr. Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Janannathpura Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 123/4), Village-Mahapura, Tehsil-Manawar, District-Dhar (MP) (B2)**

प्रस्तावित रेत खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसे आज दिनांक 06/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोविन्द प्रसाद मिश्रा, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJESH CHANDRA, Junior Manager, The M P State Mining Corporation Ltd Address Paryavas Bhawan, Blok No A 2nd Floor, Arera Hills Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	ग्राम Mahapura तसहील Manawar जिला Dhar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-1000 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 731 दिनांक 24/03/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य केशर खदानें स्वीकृत है, जो सदृश खनिज नहीं होने के कारण प्रकरण बी-2श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 731 दिनांक 24/03/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 731 दिनांक 24/03/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-..... के सरल	

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

	क्रमांक—.... पर दर्ज है ।
--	---------------------------

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र से पश्चिम दिशा में लगभग 256 मी. पर रोड ब्रिज है**, जो मेजर ब्रिज है, एवं एक अन्य रपट जैसी अस्थायी प्रकृति की संरचना लगभग 454 मी. पर **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।** सेड गार्डलाइन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

17. Case No. 1301/2013 Shri Purusotam Patidar, M.G Road Anjad, Teh.-Anjad, Dist.-Badwani (M.P.) Pin Code. 451556 Environment Clearance for approval of 0.95 Hectares Stone/Boulder Quarry at Vill.-Palasiya, Teh.-Anjad, Dist.-Badwani (M.P.)-EC AMENDMENT.

प्रकरण में सिया के पत्र क्रमांक 1703 दिनांक 07/11/2014 के द्वारा रकबा 2.00 हे. क्षेत्र पर उत्पादन क्षमता पत्थर बोल्टर 4200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म-6 के साथ लीज नवीनीकरण आदेश दिनांक 1905 दिनांक 20/07/2023 द्वारा 0.95 क्षेत्र पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अनुरूप परियोजना प्रस्तावक ने ईएमपी, पीएफआर एवं अनुमोदिन खनन योजना प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 1703 दिनांक 07/11/2014 को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति रकबा संशोधित किये जाने हेतु फार्म-4 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण समिति की दिनांक 06/03/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पुरषोत्तम पाटिदार, ऑन लाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 06 मार्च 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भ में उत्खनिपट्टा कार्यालय कलेक्टर जिला बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 673/खनिज/2003 दिनांक 08-07-2003 द्वारा 10 वर्ष 2003 से 2013 तक रकबा 2.0 हेक्टेयर पर स्वीकृत किया गया था। जिसके उपरांत उत्खनिपट्टे का नवीनीकरण संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आदेश पत्र क्रमांक 13832-33/खनिज दिनांक 25-07-2014 द्वारा रकबा 2.0 हेक्टेयर पर 10 वर्ष अवधि दिनांक 04-08-2013 से 03-08-2023 तक के लिए किया गया था। इसके बाद कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बड़वानी द्वारा पत्र क्रमांक 1905/खनिज/2023 दिनांक 20-07-2023 के माध्यम से उत्खनिपट्टे का नवीनीकरण मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 6 के तहत नियम 18 (2) में मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 23-03-2013 संसोधन के तहत रकबा 2.0 हेक्टेयर से कम कर 0.95 हेक्टेयर पर 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया गया। पत्र में उल्लेख है कि खदान क्षेत्र से लगभग 50 मी. की दूरी पर शनिदेव मंदिर का भोजन कक्ष एवं लगभग 20 मी. पर निर्माणाधिन अस्पताल है, जिनकी नियमानुसार दूरी छोड़ते हुये खदान क्षेत्र 2.0 हे. से कम कर 0.95 हे. कर दिया गया है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षित माईनिंग प्लान को प्रस्तुत किया गया जो रॉक ब्रेकर पर आधारित है। समिति द्वारा पूर्व प्रदाय पर्यावरण स्वीकृति का पर्यावरण संबंधि शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया जिसमें पाया कि खदान क्षेत्र के अंदर अल्प मात्रा में पौधा रोपण किया गया है एवं सामाजिक कार्य, भी आंशिक रूप से करना पाया गया। समिति ने निर्देश दिये कि शेष बचे हुये पौधारोपण कार्य को जुलाई 2014 तक पूर्ण किया जावें एवं अन्य सामाजिक कार्य एवं फेन्सिंग कार्य को अक्टूबर नवम्बर 2024 तक पूरा करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सामाजिक कार्य 0.80 लाख रुपये का प्रस्तुत किया जो पूर्व कार्य के अतिरिक्त है एवं 1100 पौधे लगाये जाना प्रस्तावित है जिसे जुलाई-अगस्त 2024 में पूर्ण किये जाने की शर्तों के अनुसार उत्पादन क्षमता पत्थर बोल्डर 4200 घनमीटर/वर्ष के साथ अनुशंसित किया जाता है।

18. **Csae no. 6233/20 M/s Jai Shree Shyam Minerals, Infront of Police Station, Bamhni Banjar, Tehsil –Bichhiya, Dist. Mandla, MP Prior Environment Clearance for Expansion of Dolomite Mine in an area of 4.48 ha. (From 50000 to 154814 tonne per annum) (Khasra No. 51, 52, 53, 55/1), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bichhiya, Dist. Mandla (MP)-TOR Validity Extension.**

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर संबंधित दस्तावेजों के साथ पूर्व में जारी टॉर की वैधता अवधि बढ़ाये जाने हेतु फार्म-5 में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024


प्रकरण समिति की दिनांक 06/03/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi, Online from M/s AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।


The chronology of the project:

- TOR recommended in 376th SEAC meeting dated 01-07-19.
- TOR approved in 559th SEIAA meeting dated 06-08-19.
- Letter no. 1968-69/SEIAA/19 dated 31-08-19 to PP - request to submit EIA report as per SEAC recommendation within stipulated period of submission.
- Public Hearing sent to SEAC vide letter no. 3025-26, dated 28-02-23.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तुत प्रकरण पूर्व में जारी टॉर की वैधता अवधि बढ़ाये जाने का है। इस संबंध में उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंडला का पत्र क्रमांक 1790 दिनांक 05/12/2023 टॉर अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने की अनुशंसा हेतु पत्र सदस्य सचिव सेक/सिया को प्रेषित किया है, पत्र में उल्लेख है कि आवेदक द्वारा स्वीकृत उत्खनित पट्टा क्षेत्र में खनिज डोलामाईट का उत्पादन क्षमता 50,000 से 1,54,816 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष विस्तार किये जाने हेतु सिया के समक्ष आवेदन किया गया था आवेदन के संबंध में दिनांक 08/09/2019 को टॉर जारी हुआ था परन्तु कोविड महामारी के शुरुवात होने एवं महामारी के दौरान आवेदक का स्वास्थ्य खराब होने से ईआईए की प्रक्रिया में विलंब हो गया है। ईआईए कन्सलटेंट द्वारा अक्टूबर-2021 से दिसंबर-2021 तक स्वीकृत खदान क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्र की मॉनिटरिंग की गई एवं ड्राफ्ट ईआईए बनाकर जमा की गई तदुपरांत दिनांक 17/01/2023 को लोक सुनवाई आयोजित की गई एवं कार्यवाही विवरण अप्रैल-2023 में प्राप्त हुआ। तत्समय पेसा एक्ट लागू हो जाने से आवेदक को पुनः ग्राम सभा की एनओसी प्राप्त करनी पड़ी इस कार्य में अधिक समय व्यतीत होने के कारण आवेदक का टॉर एक्सटेन्सन दिनांक 17/08/2023 को समाप्त हो गया है, एवं सिया में अंतिम ईआईए प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया शेष है। आवेदक द्वारा सिया कमेटी से ओ.एम (08/06/2022)के अनुसार 01 वर्ष की अवधि बढ़ाने का आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरणीय सलाहकार के उपरोक्त आवेदन को मान्य करते हुये टॉर अवधि 01 वर्ष बढ़ाये जाने की अनुशंसा की जाती है।


(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव


(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘B’

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 मार्च 2024

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 मार्च 2024

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 06 मार्च 2024

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिख जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

729वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 06 मार्च 2024

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई क्षतिवत्तम उतममकपदह क्षतिवत्तम तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे